Important News: World

1. यूरोपीय संघ (EU) डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की कि वे **डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)** पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंच गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- **डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)** बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना और अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और उनके मौलिक अधिकारों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने" के लिए मजबूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है।
- यह तकनीकी कंपनियों द्वारा स्व-नियमन के युग को समाप्त करने का प्रयास करता है, और 'इस सिद्धांत को व्यावहारिक प्रभाव देता है कि जो अवैध ऑफ़लाइन है, वह ऑनलाइन अवैध होना चाहिए'।
- यह "सरल वेबसाइटों से लेकर इंटरनेट अवसंरचना सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक, ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी" पर लागू होगा।

पृष्ठभूमि:

- आयोग ने **डिजिटल बाजार अधिनियम** के प्रस्ताव के साथ 15 दिसंबर 2020 को **डिजिटल सेवा अधिनियम** पर अपना प्रस्ताव रखा, जिस पर 22 मार्च 2022 को यूरोपीय संसद और परिषद एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचे।
- इन पर राजनीतिक समझौते यूरोपीय संघ में एक सुरक्षित, खुला और निष्पक्ष ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दो फाइलें एक साथ काम करेंगी।

नोट: भारत में, इसी तरह के मुद्दे पर एक विधेयक (डेटा संरक्षण विधेयक 2019) संसद में लंबित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर हाट दो साल बाद खुला

चर्चा में क्यों?

- मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर **बॉर्डर हाट** दो साल के अंतराल के बाद खोला गया।

प्रमुख बिंदु

- मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में बलात और बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के दलोरा में लौवाघर के बीच बॉर्डर हाट खोलने का निर्णय संयुक्त बॉर्डर हाट प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया था।
- वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश में सात स्थापित बॉर्डर हाट हैं और नौ और नए बॉर्डर हाट पाइपलाइन में हैं।
- **बॉर्डर हाट** सीमा के दोनों ओर के स्थानीय निवासियों को स्थानीय उत्पादों का व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं।

नोट: 2021 तक, भारत के पास केवल 4 बिम्सटेक (BIMSTEC) पड़ोसियों, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ बॉर्डर हाट हैं।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

Important News: India

3. भारत की तकनीकी ताकत का दोहन करने के लिए CSIR और आईक्रिएट (iCreate) के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात सरकार के प्रमुख प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर - **आईक्रिएट (iCreate) (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी)** और **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन के तहत, CSIR और आईक्रिएट देश में उद्यमियों और नवोन्मेषकों के लिए संयुक्त संसाधन उपलब्ध करके भरोसेमंद तकनीकी स्टार्ट-अप के लिए एक सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित करने का विचार है।
- ऐसे स्टार्ट-अप CSIR के उपकरण, सुविधाओं और वैज्ञानिक मानवशक्ति का उपयोग करेंगे।
- CSIR उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा सहायता प्रदान करेगा और भारत के अभिनव स्टार्ट-अप को वित्तीय रूप से समर्थन देने के तरीकों का पता लगाएगा।

आईक्रिएट (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी) के बारे में:

- यह गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है और तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्ट-अप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है।
- अब तक इसने 412 से अधिक नवाचारों और उच्च स्तर के 30 पेटेंट से अधिक, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट मॉडल को समर्थन दिया है, जो उन्हें परामर्शकर्ता, बाजार और धन से जोड़ता है।
- यह भारत में सिस्को की सबसे बड़ी नवाचार प्रयोगशाला का स्थान है और अमेरिका, इजराइल एवं अन्य देशों के प्रमुख संस्थानों के साथ इसकी साझेदारी है।

भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:

- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है।
- भारत में लगभग 20,000 स्टार्टअप; इनमें से लगभग 4,750 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप हैं।

अन्य संबंधित पहल:

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम
- मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज

स्रोत: PIB

4. केंद्र ने केंद्रीय विद्यालयों में MP कोटा समाप्त किया, प्रवेश दिशानिर्देशों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने **केन्द्रीय विद्यालयों (KV)** में प्रवेश के लिए विवेकाधीन संसद सदस्य (MP) कोटा खत्म कर दिया है, और संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए हैं।

प्रमुख बिंदु

- KVS विशेष व्यवस्था प्रवेश योजना, या MP कोटा के तहत, एक संसद सदस्य को कक्षा 1 से 9 में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश करने की शक्ति थी।
- सांसद के अलावा अन्य कोटा, KVS ने अन्य आरक्षणों को भी हटा दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चे, सांसदों और सेवानिवृत्त KV कर्मचारियों के बच्चों और आश्रित पोते, और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटा शामिल हैं।
- नए कोटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स जैसे समूह B और C केंद्रीय पुलिस संगठनों के बच्चों के लिए 50 सीटें शामिल हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा, सीमा के लिए तैनात किया गया है।
- इसके अलावा, KVS ने प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर PM केयर्स योजना के तहत शामिल बच्चों को भी शामिल किया है।

स्रोत: HT

5. कोवैक्सिन, कॉर्बेवैक्स को 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली

चर्चा में क्यों?

- **भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI)** 5-12 आयु वर्ग के लोगों के लिए कॉर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA), 6-12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सिन और 12 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ZyCoV-D प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने भारत बायोटेक के COVID वैक्सीन कोवैक्सिन को 6-12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया है।
- इसके अलावा DCGI ने 5-12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण भी प्रदान किया।
- कैडिला हेल्थ के ZyCoV-D को 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है।

नोट: विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 24 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया जा रहा है। 2022 का विषय 'सभी के लिए लंबा जीवन' है।

स्रोत: ET

Important News: State

6. तमिलनाडु ने कुलपतियों के नाम रखने के राज्यपाल की शक्तियों को छीनने के लिए 2 विधेयक पारित किए

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल से राज्य सरकार को अपने कुलपति नियुक्त करने की शक्ति हस्तांतरित करने के लिए 13 विश्वविद्यालयों के कानूनों में संशोधन के लिए दो विधेयक पारित किए।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार के पास कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति की कमी का उच्च शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ा है।
- उन्होंने बताया कि गुजरात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य, राज्य सरकार एक खोज समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों से कुलपति नियुक्त कर रही है।
- प्रस्तावित विधेयक इस बात पर जोर देते हैं कि "कुलपति की हर नियुक्ति सरकार द्वारा तीन नामों के पैनल से की जाएगी" एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित।
- UGC (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, "विजिटर / चांसलर" - ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल - होंगे खोज-सह-चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करें।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत, भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विज़िटर होंगे।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा विज़िटर की हैसियत से नियुक्त किया जाता है।
- कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट: इसके अलावा, केंद्र-राज्य संबंधों को देखने के लिए केंद्र द्वारा 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को वीसी नियुक्त करने की शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए क्योंकि "कार्यों और शक्तियों का टकराव होगा"। उन्नीस राज्यों ने आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अपनी टिप्पणी की पेशकश की।

स्रोत: TOI

Important News: Defence

7. सरकार ने सैन्य खरीद में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को और बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020** को **रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)** द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर संशोधित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग से रक्षा उपकरण/ सोर्सिंग का आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए और DAC/ रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।
- वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार और वित्तीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी (IPBG) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- इसके अलावा, भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) से बयाना राशि जमा (EMD) की आवश्यकता नहीं है।
- एक ऐसे पारितंत्र की रचना के लिए जो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों, स्टार्टअप और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देता है और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है, **iDEX फ्रेमवर्क** अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- देश के नवोदित स्टार्टअप प्रतिभा पूल को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के दोहरे मंत्रों में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए DAP 2020 की iDEX प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ।
- DAP -2020 की मेक-2 प्रक्रिया, जिसमें प्रोटोटाइप विकास के चरण में उद्योग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण शामिल है, को प्रोटोटाइप के एकल चरण के समग्र परीक्षणों को शामिल करके और प्रत्यायोजित मामलों में प्रारंभिक खरीद के लिए मात्रा की जांच और स्केलिंग के साथ वितरण को सरल बनाया गया है।

स्रोत: इंडिया टुडे

Important News: Days

8. 28 अप्रैल, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रत्येक 28 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2022 सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह सुरक्षित काम और काम से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों के आयामों और परिणामों के बारे में जागरूकता के बारे में चिंतित है; **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH)** को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंडा पर रखने के लिए।
- विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस पहली बार 2003 में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** द्वारा मनाया गया था।

स्रोत: un.org